The driver was also injured. He was also taken to the same hospital. ...*(Interruptions)*... And from the hospital, sometime in the night, he quietly slipped away and disappeared. This is the kind of arrangement we have in our Capital city!

And the second question that you asked was about speed checks. Speed checks are taking place now. They have been installed at several places and we hope that this will become more effective.

डाक व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जाना

*242. **श्री गोविन्दराम मिरीः***
श्री शिव चरण सिंहः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार डाक व्यवस्था में व्याप्त कुप्रबंध को दूर करने के उद्देश्य से उसका आधुनिकीकरण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी० खलप): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल रखा गया है।

विवरण

टैक्नालॉजी का समावेश करके डाक प्रणाली को आधुनिक बनाना डाक विभाग की आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है। यह उद्देश्य काउंटर सेवाओं पर विशेष जोर देते हुए विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में कम्प्यूटर पर आधारित टैक्नालॉजी की शुरूआत करके प्राप्त किया जा रहा है।

डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों का उद्देश्य निम्नलिखित प्रदान करना है:

(क) ग्राहकों के लिए अधिक कार्यकुशल तथा उत्तरदायी काउंटर सेवाएं;

(ख) आइडेंटीफाइड कस्टमर ग्रुपों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नई मूल्यवर्धित सेवाएं; और

(ग) कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने तथा कार्य की बोझिलता समाप्त करने के लिए काम और काम की परिस्थितियों के बेहतर अध्ययन से कार्यकुशलता बढ़ाने के साथ-साथ आधुनिक तथा स्वच्छ कार्य वातावरण।

इस प्रयोजन के लिए तैयार किए गए मशीनीकरण व आधुनिकीकरण के विशिष्ट कार्यक्रम इस प्रकार हैं:—

— कम्प्यूटर पर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की शुरूआत।

— महत्वपूर्ण बड़े केन्द्रों में मेल प्रोसेसिंग को ऑटोमेटिक बनाना।

— मनीआर्डर शीघ्र भेजने तथा अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए वैरी स्माल अपरचर टर्मिनल्स (वी०एस०ए०टी०) नेटवर्क की स्थापना।

— बचत बैंक, डाक जीवन बीमा (पी०एल०आई०) और स्पीड पोस्ट आपरेशन्स के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग।

— कार्य के वातावरण को बेहतर बना कर तथा ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करके काउंटर सेवाओं और फ्रंट ऑफिस का आधुनिकीकरण।

— काम करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और काम की बोझिलता को समाप्त करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण डाकघरों में उन्नत ऑपरेशनल इक्विपमेंट प्रदान करना।

मशीनीकरण और आधुनिकीकरण की स्कीमों में जिस सीमा तक लक्ष्य प्राप्त किया गया, इस प्रयोजन हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में मुहैया कराया गया योजना परिव्यय तथा 31 मार्च, 1996 तक इस्तेमाल की गई धनराशि का विवरण क्रमशः अनुबंध-I, अनुबंध-II, अनुबंध-III, में दिया गया है। वर्ष 1996-97 के दौरान, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है, आधुनिकीकरण के ये कार्यक्रम जारी रखे गए हैं।

उपभोक्ताओं के एक बड़े वर्ग को, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के उपअभोक्ता भी शामिल हैं, टेक्नालॉजी का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जो स्कीमें शुरू की गई हैं, उनका व्यापक विस्तार और अधिकतम उपयोग करने के लिए उन्हें कंसोलिडेट किया जा रहा है।

अनुपत्र-I

आठवीं योजनावधि के प्रथम चार वर्षों के दौरान स्कीमों में वास्तविक लक्ष्य प्राप्ति

क्रम० सं०	स्कीम का नाम	आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	31.3.96 की स्थिति के अनुसार उपलब्धि
1.	**प्रौद्योगिकी उन्नयन**		
	(क) बहुद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना	5000	2300
	(ख) मेल हैंडलिंग का मशीनीकरण	3	2
	(ग) वीएसएटी नेटवर्क की स्थापना	75 स्टेशन	61 स्टेशन
	(घ) डाकघरों का आधुनिकीकरण	कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं	481
	(ङ) स्पीड पोस्ट के लिए ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली की स्थापना	-वही-	2
	(च) इलेक्ट्रानिक फ्रैंकिंग मशीनें	-वही-	40
	(छ) मशीन निर्मित हैंड कैंसलर	25,000	18,000
	(ज) डाक-टिकट कैंसलिंग मशीनें	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	255
2.	**डाक जीवन बीमा**		
	(क) सर्किलों में डाक जीवन बीमा कार्य का कम्प्यूटरीकरण	5 प्रधान डाकघर	5 प्रधान डाकघर
	(ख) बचत बैंक नियंत्रण संगठन	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	107
4.	**सामग्री प्रबंध**		
	(क) पोस्टल स्टोर डिपो का कम्प्यूटरीकरण	46	46

अनुपत्र II

मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 में मुहैया कराया गया योजना परिव्यय।

योजना	आठवीं योजना का परिव्यय (करोड़ रुपयों में)	
1. प्रौद्योगिकी उन्नयन	—	132.53
2. डाक जीवन बीमा	—	5.77
3. राष्ट्रीय बचत	—	2.50
4. सामग्री प्रबंध	—	4.90
कुलः		145.70

अनुपत्र-III

मशीनीकरण और आधुनिकीकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 31 मार्च, 1996 तक इस्तेमाल किया गया फंड

योजना	31.3.96 तक व्यय (करोड़ रुपयों में)	
1. प्रौद्योगिकी उन्नयन	—	95.27
2. डाक जीवन बीमा	—	2.17
3. राष्ट्रीय बचत	—	0.98
4. सामग्री प्रबंध	—	1.76
कुलः		100.18

SHRI SATISH AGARWAL: Portfolio changed!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): No, no; the hon. Minister has sought the permission.

SHRI MD. SALIM: No, communication gap!

श्री गोविन्दराम मिरीः उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का लिखित उत्तर सही नहीं आया है। मैंने यह पूछा था कि क्या सरकार डाक व्यवस्था में व्याप्त कुप्रबन्ध, मिसमैनेजमैंट को दूर करने के उद्देश्य से उसके आधुनिकीकरण करने पर विचार कर रही है, इसका जवाब सही नहीं आया है। एनेक्सर-1 में दर्शाया गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना जो खत्म होने जा रही है इसमें डाकघरों के आधुनिकीकरण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। एक तरफ तो हम आधुनिकीकरण के नाम पर बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, बिना लक्ष्य के हम कैसे अपने उद्देश्यों तक पहुंच सकते हैं?

इस तरह स्पीड पोस्ट के लिए ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली की स्थापना की गई है। उसका भी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। इसी तरह से इलेक्ट्रानिक फ्रैंकिंग मशीनों का टारगेट निर्धारित नहीं है। डाक-टिकट कैंसलिंग मशीनों का भी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। बचत बैंक नियंत्रण संगठन कम्प्यूटरीकरण का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर किस प्रणाली पर हमारा भारतीय डाक-तार विभाग काम करने जा रहा है और यह लक्ष्य निर्धारित न करने का क्या कारण है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में क्या इन मुद्दों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? यदि हां तो वे क्या हैं? मेरे प्रश्न का यह भाग "अ" है और भाग "ब" में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए जो 132.53 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसमें से मात्र 95.27 करोड़ खर्च किया गया। इसका अर्थ यह है कि 37.26 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया गया। इसी तरह से डाक जीवन बीमा में 5.77 रुपये का लक्ष्य था जिसमें से केवल 2.17 करोड़ रुपया खर्च किया गया। तो 3.60 करोड़ यह है जो.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Okay, Mr. Miri Let the Minister answer. Don't put the two supplementaries together.

श्री गोविन्दराम मिरीः महोदय, इसी तरह से राष्ट्रीय बचत में 2.50 करोड़ रुपये का लक्ष्य था जिसमें से केवल 98 लाख रुपए खर्च किए गए और सामग्री प्रबंध में 4.90 करोड़ रुपए का लक्ष्य था जिसमें केवल 1.76 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो यह विभाग वित्तीय संकट का रोना रोता है और दूसरी तरफ उसे जो पैसा दिया जाता है वह उसका उपयोग नहीं कर पाता। तो इसका क्या कारण है?

श्री रमाकान्त डी० खलपः उपसभाध्यक्ष महोदय,

यह सच है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसमें से सारा पैसा खर्च नहीं हुआ। The Eighth Plan outlay for upgradation of technology, postal life insurance, national savings and material management was Rs. 145.70 crores. Out of this, the amount actually spent was Rs. 100.18 crores. The reason was that the plan was to computerise the postal services in different ways throughout the country. The hon. Member may kindly note this this is a vast country and the postal services network is so vast and so wide that it is not really possible to utilise everything at one time.

Secondly, upgradation of technology cannot be achieved through one source alone. Since a beginning was made, the help of different organisations had to be taken. In the process in certain places we had to watch the performance, whatever work that was done. As a reuslt of that, in some places we found that the work could not go on according to the original plan. Though no specific target was set for modernisation of post-offices, my learned colleague may kindly see that targets were set for things which he has not mentioned. In the annexure we have stated that the target for installation of multi-purpose counter machines was 5,000,... (*Interruptions*)...

SHRI GOVINDRAM MIRI: Sir, I have mentioned only those... (*Interruptions*)...

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: ... the target for mechanisation of mail handling was three; the target for installation of VSAT network was 75; the target for machine-made hand cancellor was 25,000 and so on. The targets were laid for some things and for some others the targets were not laid down. But the work is going on at quite a satisfactory speed. We shall see to it that whatever baklog has remained will be completed within the shortest possible time. (*Interrputions*)...

SHRI GOVINDRAM MIRI: Sir, he has not mentioned about the Ninth Plan.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Minister, would like to say something about the Ninth Plan? What is the target? What is the allocation?

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: Sir, as far as the Ninth Plan is concerned,.... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): As regards the Ninth Plan, he may not be able to answser because it has not taken a final shape. You put your second supplementary.

श्री गोविन्दराम मिरी: सर, डाक विभाग के आधुनिकीकरण के अनेक दावों के बावजूद आज भी यह देखने में आ रहा है कि ये जो प्राइवेट कूरियर सर्विसेज हैं, ये मशरूम की तरह नित्य दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण, मैं यह समझता हूं कि हमारी डाक विभाग की जो कार्य प्रणाली है उसमें दोष है और उनकी शिथिलता के कारण ये बढ़ रहे हैं। महोदय, इन्होंने लूट मचाई हुई है। डोमेस्टिक सर्विस के लिए ये सैकड़ों रुपए चार्ज करते हैं और ओवर-सीज डाक के लिए हजारों रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये फल और फूल रहे हैं। और हम अनेक हाईब्रिड, हाई स्पीड तमाम जो हम कागज़ों पर भी दावा कर रहे हैं व्यवहार में वह नहीं लाए जा रहे हैं। इसके कारण इस विभाग के रेवेन्यु या आय पर सीधा प्रहार हो रहा है। उसकी एफीशिएंसी बढ़ाने के लिए आप क्या-क्या कर रहे हैं? दूसरा मेरा कहना है कि शिकयतें ऐसी मिलती हैं कि क्षुब्ध कर्मचारी जिनके ग्रीवासेज़ दूर नहीं होते हैं वे डाक को पूरा ब्लक के बल्क जला देते है, फैंक देते हैं, पानी में फैंक देते हैं और डाक नहीं पहुंचाते हैं तो बिना कर्मचारियों के, यह रेल के बाद दूसरा बढ़ा संगठन है, तो टार्गेट तक नहीं पहुंच सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनको मेपेड देने के लिए, यूनिफार्म देने के लिए और उनको कुछ रिवार्ड्ज़ इंसेंटिव्ज़ पैकेज देने के लिए विभाग ने कोई कार्यक्रम बनाए हैं और कहां तक वह लक्ष्य में पहुंचे हैं? इसको बताने का कष्ट करें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): The hon. Member has raised two points.

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: He has raised two points. But both these points appear to be beyond the scope of

the question. In fact, this question relates to what we are doing in regard to modernising the postal services.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): One thing is relevant. Now private operators are delivering consignments. They are doing a very efficient service. Why can't the Postal Department do it? This is a relevant question.

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: This part of the question is relevant. The second part of his question was whether they would be given a moped, uniform and all that, it relates to....

SHRI GOVINDRAM MIRI: What are they doing to increase the efficiency of the workers?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Let him answer.

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: Sir, I would like to tell the House that every possible step is being taken to modernise the postal services. Computerisation is one of the most important steps. So far as his question regarding private courier service is concerned, at the moment, thre is no law in existence to control the private courier service. As a result, they are blooming and growing. They are doing all the work.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Minister the private courier service is doing a very efficient service in delivering letters and parcels, Why can't the Postal Department do it? That is the question of the hon. member. If the Postal Department is efficient, they will not be able to compete with the Postal Department.

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: Sir, it is not so. The quantum of work is so much that probably there is room for private courier service in our country. But the point is, you cannot blame the postal services. No doubt, there are certain handicaps, there are certain drawbacks and there are certain other aspects. We have to consider the Postal Department as a whole. If you look at the Postal Department, it is catering to the needs of our people throughout the country. Our postmen are going to the remotest villages of our country. It should also be considered. There may be certain instances where one postman might have thrown a bag in some river or he might have set a bag on fire, as the hon. Member has mentioned. These are very strange incidents. Such a thing happens on a very rare occasion. It depends upon the individual character of the person concerned. But that is not a reflection on the efficiency of the whole postal services. By and large, postal services are very good. But we are not satisfied with that. The Postal Department is concerned with the whole matter. Many steps have been taken in the Eighth Five Year Plan in this direction. In the Ninth Five Year Plan, more steps would be taken so that we can really comepte with the private agencies as well. Simultaneously, we are also contemplating a law to control and regulate the private courier services also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): What about the problem of employees?

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: If there are any problems, we will look into those problems.

श्री शिव चरण सिंह: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने कंप्यूर लगा दिए, धन्यवाद, आपने ये प्रोसैसिंग आटोमैटिक प्लांट लगा दिए, धन्यवाद, लेकिन आपका मनिआर्डर क्या अभी भी दो गवाहों के बगैर दिया जाता है? आपके स्पीड पोस्ट के जितने लैटर जाते है उनमें कितने कैंसल होते हैं और कितने के पैसे वापस किए जाते हैं और मैं इसी का पार्ट पूछना चाहता हूं कि हमारे 6 बड़े शहर और राज्यों की राजधानियों क्या उनमें हवाई जहाज के जरिए आप डाक भेजने की व्यवस्था किए है या करेंगे, या फिर क्यों नहीं किए, क्योंकि आधुनिकीकरण का केवलमात्र यही एक जरिया था?

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: Sir, so far as money-orders are

concerned, we have now introduced a V-SAT system. We are making use of the Satellite. This system has not been introduced in the entire country so far. We have introduced it in some places and the results are very encouraging. You can get money immediately. This particular VSAT system is also available with what is called the Hybrid Postal Services. ...*(Interruptions)*...

श्री शिवचरण सिंह: मान्यवर, ये सैटेलाइट से रुपया भेजने की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन पोस्टमेन जो डिलीवरी देता है, वह दो गवाह चाहता है। मान्यवर, जब से पोस्ट एंड टेलिग्राम एक्ट लागू हुआ है, तब से आज तक यह व्यवस्था चल रही है। अब इस का क्या इलाज है? ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Let the Minister reply...*(Interruptions)*...

श्री शिव चरण सिंह: मान्यवर, संभवतः मेरे प्रश्न को मंत्री जी समझे नहीं?

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: मैं समझ गया आप के प्रश्न को।

The question of witnesses will have to be looked into in a larger perspective. How can you say that the postman will always go to the right person? An imposter could come forward and say, "I am the man to whom the money has been sent, give it to me." If he is not very certain about the identity of the concerned person, then he will have to rely on some witness. It is a question of money. The poor man, tomorrow, could be charged of misappropriating the money. He needs some proof.

श्री शिवचरण सिंह: मान्यवर, मनी-आर्डरों में 50 प्रतिशत संख्या फौजियों की होती है और आज भी आर्मी पर्सनल्स की फेमिलीज़ आयडेंटीफाइड हैं, लेकिन उनकी फेमिलीज जो जो मनी-आर्डर आता है...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Let the Minister complete his reply.

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: It is a question of money. Whether it is ten rupees or thousand rupees, it should reach the right person. It could be pension money or it could be that somebody's son working in some distant place, where he sweats and earns some money, would be wanting to send it to his family. For this purpose some steps are being taken to identify the concerned person. People would be willing. We are not asking for witnesses from outside. Some neighbour can be a witness. I think we should not grudge this. Otherwise, we will have to have an identity card for everybody so that we know who the person is and the money could be given. Please bear with us. This system is meant for the benefit of the people.

श्री शिवचरण सिंह: मान्यवर, देश की राजधानी और महानगरों को हवाई सेवा से डाक भेजने की व्यवस्था के संबंध में तो उत्तर आना चाहिए क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेन्ट है?

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: We will take note of this.

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Sir, I come from Kanyakumari. I made representations more than three, four times for speed post in Kanyakumari. It is a historic place. I would like to know whether there is any proposal to start speed post services in Kanyakumari. We also made a lot of representations for upgradation of certain post-offices in Tamil Nadu. We sent a representation to the Tamil Nadu Postmaster-General and the Telecommunications Department. But we did not receive a single letter from them. A function was held in Chennai last week. The hon. Minister for Finance was invited. The hon. Minister for Defence was not invited. I believe he demanded from the concerned officer...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): What is your supplementary question? Your supplementary question should be related to the original question. You wanted to have speed post facility in Kanyakumari. Don't bring in politics here... *Interruptions)*...

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: There is a particular village ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): While putting supplementaries, do not raise individual issues. The Minsiter will reply to your question on Kanyakumari ...*Interruptions)*...

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: As far as providing speed post facility to Kanyakumari is concerned, I cannot give an assurance right away. But I would like to tell the hon. Member that we wish to start this facility not only in Kanyakumari but in as many places as possible in the country. Regarding the second question that no effort was made to modernise Tamil Nadu Post-Offices, I disagree with it. Let me provide you with details. The number of multi-purpose counter machines installed in Tamil Nadu is 198. I have the list for the entire counrty. I also have the list of the number of post-offices that were modernised in Tamil Nadu. The number is 38. As regards the rest of the States, somewhere it is 38, somewhere it is 10, somewhere it is 28 and so on. In Tamil Nadu, the number is 38 and in UP, it is 33. Note the difference. In West Bengal it is 20, Rajasthan 24, Punjab 12, Orissa 9, North-East 17, Maharashtra 77, Madhya Pradesh 23, Kerala 23, Karnataka 28 and so on. If you want the names also, I can give you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): No no, if the hon. Member wants, you can send it to the hon. Member.

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: This allegation is not correct that Tamil Nadu is not getting modernised services.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Okay.

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: Thirty eight post offices for the benefit of my friend..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Minsiter, you have answered that point.

SHRI PARAG CHALIHA: Sir, we are discussing the matter of modernisation in post offices. I am sorry to refer to some classical traditions going on in the North-East including Assam. In reply to a question in March last year, the total number of post offices with computer-based contract machines was six in Assam. In Tripura it was one, in Manipur it was one, in Nagaland it was one, in Meghalaya it was two, in Mizoram it was one. Sir, just to speak about my own fate with this communication system, the speed post letters coming to me and sent by me reach may place, Sibsagar district headquarters of Assam in four to five days. The normal post takes beyond 12 to 15 days. In my district headquarters at Sibsagar the postage bags are carried only in gunny bags; not by bullock carts but by human carts. Therefore, may I ask the Minsiter, if he would kindly ensure that special measures are taken that we in the North-East, not to speak about the age-old facilities, are allowed to think about something on what is known as modern postal services.

Will he take some concrete steps about that?

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: Sir, for the North-East region, 10 per cent of the Annual Plan funds of the Department of Posts has been reserved for North-East. This is so far as funds are concerned. Now multi-purpose counter machines are installed in North-East, I may apprise the hon. Member that as of today we have 30 multi-purpose counter machines in the Nort-East. In Assam, the figure is 60 and not five as the hon. Member mentioned. In Assam, the number of multi-purpose counter machines are 60 and in the North-East it is 30. Then I can also give you the list of post offices modernised in Assam and North-East circles. If you want all these figures, I can give you. Then, Sir, the total modernised programmes for post offices, the post offices modernised—in fact, the figure is a little old, it is 31st

March, 1996—in Assam are ten and in the North-East 17 offices were modernised. If you want the names in Assam, I can give you. They are Assam Sachivalaya Post Office, Guwahati Post G.P.O. Jorhat S.P.O, Nagaon S.P.O Dibrugarh S.P.O., Fancy Bazaar S.P.O., Silchar S.P.O., Sibsagar S.P.O.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): No, no, the figures given by hon. Member and yours vary. If the Member feels that he is satisfied, then it is all right.

Indigenously built Light Combat Aircraft

*243. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the future of Light Combat Aircraft indigenously built in November, 1995 is still uncertain;

(b) the reasons for not developing it although it was the lightest aircraft known; and

(c) the measures proposed to encourage indigenous production of light combat aircraft at an early date?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) and (b) No, Sir. The indigenous light combat aircraft (LCA) which was rolled out from its hangar in November 1995, is in advanced stages of system integration and ground tests before its maiden flight test planned in November, 1997.

(c) Capability of design and infrastructure for fabrication/production and testing of various components/sub-systems and for integration of LCA have already been established in more than 100 work centres in laboratories of Defence Research and Development Organisation, industry, research institutions in other sectors, academic institutions and universities. The programme is being constantly monitored for prompt debottle-necking and adequate funding is being provided by the Government to facilitate indigenous production of LCA by the year 2002.

डा० वाई लक्ष्मी प्रसादः उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि नवम्बर, 1995 में देश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमानों का भविष्य अब भी अनिश्चित है। **(व्यवधान)**

SHRI N.V.N. SOMU: Sir, translation is not coming.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): The hon. Minister is saying that translation is not coming. Mr. Somu, the Secretariat will find it out. It is now coming.

डा० वाई लक्ष्मी प्रसादः धन्यवाद सर। मंत्री जी ने भविष्य के बारे में अनिश्चितता के बारे में नहीं कहा, इसलिए सुनिश्चित है। मगर मेरा स्पष्ट कहना यह है कि आने वाले 10-15 सालों में हमें 350 या 400 लड़ाकू विमानों की आवश्यकता होगी। हमारे पास विदेशों से खरीदने के लिए इतने पैसे भी नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह निश्चित कालावधि नवम्बर, 1997 तक जो बताई गई है, क्या यह कालावधि पहले नवम्बर, 1996 नहीं थीं? अगर नवम्बर, 1996 थी तो इसे क्यों बढ़ाया गया है अगर नहीं तो यह नवम्बर, 1997 निश्चित है।

SHRI N.V.N. SOMU: Sir, the question of the hon. Member concerns delay in fund allotment. Even in developed countries, development and induction of fighter aircraft is a time-consuming affair. It normally takes 15-20 years. When we take all these factors into consideration, we cannot say that there has been any unreasonable delay in the LCA programme. Secondly, the LCA project is planned in two phases. Phase-I consists of technology demonstration and development of prototypes. The Government has allotted Rs. 2,188 crores for Phase-I. Phase-II is expected to lead to production of aircraft and transfer of technology to HAL. The allocation made for Phase-II is Rs. 2,700 crores. Hence, there are sufficient funds and there is also no delay.

डा० वाई लक्ष्मी प्रसादः उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी वायु सेना में जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स का अभाव है जिसके कारण पिछले तीन सालों में 85 लड़ाकू विमानों